47

दैनिक पंजाब केसरी, जयपुर

17 8 OCT 2019

पीडब्ल्यूडी ने रोके आरएसआरडीसी के 460 करोड़

विडम्बना

- मार्जिन मनी की राशि न मिलने से गड़बड़ाई आर्थिक स्थिति

पंजाब केसरी/जयपुर

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और राजस्थान सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसी) में मार्जिन मनी को लेकर ठनी हुई है। पीडब्ल्यूडी आरएसआरडीसी के हक के मार्जिन मनी के करीब 450 करोड़ रुपए अटका कर बैठी है जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। हालांकि सरकार बदलने के बाद जब वित्त विभाग तक यह बात पहुंची तो आरएसआरडीसी को 500 करोड़ रुपए में से मात्र 40 करोड़ रुपए मिले। इधर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मार्जिन मनी के सवाल को ही सिरे से खारिज कर रहे हैं। खास बात यह है कि पीडब्ल्यूडी में से ही आरएसआरडीसी का गठन हुआ है यानी कि परोक्ष रूप से पीडब्ल्यूडी आरएसआरडीसी की संरक्षक है।

बीच में आरएसआरडीसी की खराब माली हालत के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन तक देना भारी पड़ने लगा था,उस पर भी सड़क निर्माण करने वाली फर्मों की देनदारियां ज्यादा बढ़ गई थी। बैंक लोन की किश्तें के कारण स्थिति और ज्यादा खराब होने लग गई थी,उस स्थिति में भी पीडब्ल्यूडी ने अपनी सहभागी फर्म आरएसआरडीसी की मार्जिन मनी जारी नहीं की। वैसे जानकारों का मानें तो अगर यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं जब आरएसआरडीसी बंद होने जैसे स्थिति में आ जाएगी।

आरएसआरडीसी को मिलती है 20 प्रतिशत मार्जिन मनी

पीडब्ल्यूडी बड़ी सहभागी फर्म होने के नाते आरएसआरडीसी को सरकार की एजेंसी के तौर पर मार्जिन मनी देती है,जिससे वो सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर सके। अन्य संसाधनों की व्यवस्था आरएसआरडीसी अपने स्तर पर करती है। इनमें सड़कों पर लगने वाला टोल और बैंक लोन शामिल है। उदाहरण के तौर पर यदि सड़क निर्माण की लागत 10 करोड़ रुपए आती है तो 2 करोड़ रुपए राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी के मार्फत आरएसआरडीसी को देती है जिससे वो काम शुरू कर सके। शेष 8 करोड़ रुपए आरएसआरडीसी बैंक लोन,टोल और दूसरे संसाधनों से एकत्र करती है जिससे काम रुके नहीं। अब स्थिति यह है कि पीडब्ल्यूडी शुरू में दी जाने वाली मार्जिन मनी रोक कर बैठी है और आरएसआरडीसी बैंक के लोन से सड़कों का निर्माण करवा रही है जिस वजह से निगम की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है।

इनका कहना है

मार्जिन मनी की राशि 40 करोड़ रुपए के लगभग पीडब्ल्यूडी से आ है। शेष राशि करीब 460 करोड़ भी जल्द आने की संभावना है। राज्य सरकार का रुख इस बारे में काफी सकारात्मक है। हालांकि आरएसआरडीसी की आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है,देनदारियां काफी कम होती जा रही है।

-लोकेश कुमार,प्रबंध निदेशक,आरएसआरडीसी

मार्जिन मनी और आरएसआरडीसी को दी जाने वाली राशि के बारे मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में कोई भी पत्र विभाग को आरएसआरडीसी से नहीं मिला है। मेरी ज्वॉइनिंग से पहले यानी कि करीब दो माह पहले अगर कोई पत्र आया हो तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है

-सुनील कुमार गुप्ता,मुख्य अभियंता(पथ),पीडब्ल्यूडी